विचार बिन्दु

संयम और परिश्रम मनुष्य के दो सर्वोत्तम चिकित्सक हैं। परिश्रम से भूख तेज़ होती है और संयम अतिभोग से रोकता है। –रूसो

एंटी माइक्रोबाइल रेजिस्टेंस वैश्विक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चेतावनी है

वैश्विक स्वास्थ्य के लिए दवाओं का बेअसर होना गंभीर संकट की और इशारा है। दुनिया के चिकित्सा जगत् से जुड़े विशेषज्ञ आज इस बात को लेकर चिंतित है कि मरीज को बीमारी में दी जा रही दवाओं को बेअसर होने का आंकड़ा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोई इसे भविष्य की महामारी का कारक मान रहे हैं तो कोई इसे मेडिकल इमरजेंसी तक कहने में हिचक नहीं रहे हैं। मजे की बात यह है कि दवाओं का बेअसर होने से गरीब और अविकसित व विकासशील देश तो है ही इनके साथ ही विकसित देश भी कमोबेस इससे दो चार हो रहे हैं। भले ही उनके यहां अनावश्यक दवाएं कम लिखी जा रही हो या फिर दवाओं की बिना चिकित्सक की पर्ची के उपलब्धता लगभग नहीं के बराबर हो। आज जीवनदायिनी दवाएं तेजी से बेअसर होती जा रही है, इसका एक बड़ा कारण जहां एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक सेवन है तो दूसरा कारण दवाएं लेने के तौर-तरीके से अनविज्ञ होना या फिर जान-बूझकर लापरवाही बरतने के साथ ही खान-पान से जुड़ी गलतियां भी है। डॉक्टरों की भाषा में बात करें तो एएमआर यानी कि एंटी माइक्रोबाइल रेजिस्टेंस का चिंतनीय खतरा हो गया है। देश-विदेश के चिकित्सक एएमआर को वैश्विक महामारी का नाम देने लगे हैं। देखा जाए तो आज सबसे अधिक मौत का कारण दवाओं का बेअसर होना है। कोरोना के बाद तो एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग बहुत अधिक बढ़ा है। दरअसल कोरोना के बाद जहां एक और आम व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक सजग हुआ है तो एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग भी बढ़ा है। सर्दी, जुकाम, खांसी आदि वायरल बीमारियों में यदि भारत की बात की जाए तो 95 प्रतिशत तक एंटीबायोटिक दवाओं को ईलाज में शामिल किया जा रहा है। यह 95 प्रतिशत का आंकड़ा अतिशयोक्ति पूर्ण भले ही हो सकता है पर इसमें कोई दो राय नहीं कि चिकित्सकों द्वारा एंटीबायोटिक दवाएं धडल्ले से लिखी जा रहा है। यह तो तब है जब मेडिकल से जुड़े विभिन्न मंचों व शोध निष्कर्षों में यह खुलासा हो चुका है कि एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग स्वास्थ्य को नुकसान ही पंहुचाने लगा है तो दूसरी और बैक्टिरिया में प्रतिरोधी क्षमता विकसित होने से दवाओं का असर कम होने लगा है। भारत सरकार बार-बार यह एडवाइजरी जारी करती जा रही है कि एंटीबायोटिक दवाएं अत्यधिक आवश्यकता में ही लिखी जाएं और एंटीबायोटिक दवाएं लिखते समय मरीज को कारण और उपयोग के तरीके से अवश्य बताया जाए। इसी से हालात की गंभीरता को समझा जा सकता है। जहां तक योरोपीय देशों की बात है वहां सर्दी, जुकाम, खांसी आदि वायरल बीमारियों में एंटीबायोटिक का उपयोग ना के बराबर होता है।

आज जीवनदायिनी दवाएं तेजी से बेअसर होती जा रही है, इसका एक बड़ा कारण जहां एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक सेवन है तो दूसरा कारण दवाएं लेने के तौरतरीके से अनविज्ञ होना या फिर जानबुझकर लावपरवाही बरतने के साथ ही खान-पान से जुड़ी गलतियां भी है। डॉक्टरों की भाषा में बात करें तो एएमआर यानी कि एंटी माइक्रोबाइल रेजिस्टेंस का चिंतनीय खतरा हो गया है। देश-विदेश के चिकित्सक एएमआर को वैश्विक महामारी का नाम देने लगे हैं।

दवाओं के तेजी से बेअसर होने को लेकर देश-दुनिया के स्वास्थ्य विशेषज्ञ अत्यधिक चिंता में हैं। मेडिकल से जुड़े जर्नल द लैसेंट में इस संबंध में एक के बाद एक चेतावनी भरे लेख सामने आ रहे हैं। यहां तक कि एएमआर को मेडिकल इंमरजेंसी के रुप में देखा जाने लगा है। दरअसल कोरोना के बाद लोग थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होते ही डॉक्टर की शरण में जाने को वरियता देने लगे है। यह अच्छी बात भी है पर जिस तरह से कोरोना के दौरान और उसके बाद एंटीबायोटिक का उपयोग अधिक बढ़ा है वह चिंतनीय हो गया है। हालात यहां तक हो गए हैं कि प्रति व्यक्ति 30 प्रतिशत अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक का उपयोग होने लगा है। दवाओं का बेअसर होने का सीधा-सीधा असर किडनी, लीवर, ब्रैन, हार्ट आदि प्रभावित होने लगे हैं। इन गंभीर बीमारियों में एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम होने लगा है।

दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक डॉ. एमसी मिश्रा का कहना है कि एंटीबायोटिक दवाओं को धडल्लें से बिना डॉक्टर की प्रेसक्रेप्सन के भी सहज उपलब्धता एक प्रमुख कारण है। एएमआर के लिए किसी एक को दोष नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए चिकित्सक, केमिस्ट, आम आदमी और सरकार सभी कमोबेस जिम्मेदार है। योरोपीय देशों व अमेरिका में बिना डॉक्टर के प्रेसक्रेप्सन के केमिस्ट या अन्य स्थान से दवा उपलब्ध ही नहीं हो सकती। हमारे यहां हालात विपरीत है। ऐसे में दवाओं के बेअसर होने के खतरें को टालने के लिए समन्वित प्रयास करने होंगे। डॉक्टर, दवा विक्रेता, आम नागरिकों और सरकार को समन्वित प्रयास करने होंगे। आवश्यकता नहीं होने पर एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करने, दवा विक्रेताओं द्वारा मौखिक रुप से मांगने पर दवा नहीं देने, आम नागरिकों को सजग और स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होना होगा। इसके साथ ही सरकार को भी थोडी सख्ती करनी ही होगी ताकि सेहत के लिए जरुरी दवाएं अपना असर खोने से बच सके। नहीं तो हालात जिस तरह के आएंगे उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। केवल कहने से कि एंटीबायोटिक बेअसर होती जा रही है उससे कोई सकारात्मक समाधान नहीं हो सकेगा। अधिकांश लोग इन हालातों से अनजान है ऐसे में सरकारी व गैरसरकारी संस्थाओं को जागरुकता अभियान चलाना होगा और इस पूरे चक्र को लाईन पर लाने के लिए डॉक्टरों, दवा विक्रेताओं, सरकार और आम नागरिकों को समन्वित प्रयास करने होंगे। नहीं तो आने वाले समय में एएमआर गंभीर हालातों की और इशारा करने लगी है और कहीं ऐसा नहीं हो कि हालात हमारे हाथ से निकल जाएं। यह सीधे-सीधे भविष्य के खतरे का संकेत है और ऐसे में समय रहते समाधान खोजना ही होगा।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)

यूजीसी के ग्रेजुएशन डिग्री के लिए समय सीमा में बदलाव: एक विस्तृत विश्लेषण

प्रो. अशोक कुमार

2020 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की, जो देश की शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई। यह नीति पिछले 34 सालों में भारतीय शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा बदलाव लिया है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा को छात्र-केंद्रित, बहु-विषयक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसी क्रम में, स्नातक कार्यक्रमों की अवधि को 4 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। 4 साल की अवधि छात्रों को अपने विषय का गहन अध्ययन करने का अवसर प्रदान करती है। इससे छात्रों को व्यापक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। लेकिन यह जान कर आश्चर्य हुआ की हाल ही मे यूजीसी ने अगले सत्र से स्टूडेंट्स समय से पहले ग्रेजुएशन की डिठ्ठी हासिल कर पाएंगे।

यूजीसी ने आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटि के नेतृत्व वाली कमेटी के द्वारा सिफारिश को मंजूर कर दिया, जिसके तहत अब स्टूडेंट्स तय समय से पहले स्नातक की डिग्री हासिल कर सकेंगे। इसमें 4 वर्ष वाले स्टूडेंट्स को 3 वर्ष में और 3 वर्ष वाले स्टूडेंट्स को 2.5 वर्ष में डिग्री हासिल करने का मौका रहेगा। इसके साथ ही 3 वर्ष वाले छात्र चाहें तो 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम में इसे बदल सकेंगे। यूजीसी ने यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के तहत किया है। अगले सत्र से डिग्री प्रोग्राम में एंट्री और एक्जिट प्वाइंट का प्रावधान किया जायेगा। इसके तहत ऐसे छात्र जो जो जल्दी सीखने और समझने की क्षमता रखते हैं वे आसानी से इस योजना का लाभ उठाकर समय से पहले डिग्री प्राप्त कर पायेंगे। इससे मेधावी छात्रों को समय बचत होगी। इस बदलाव के कई फायदे हैं, जैसे कि छात्र कम समय में अपनी डिग्री पूरी कर पाएंगे, जिससे वे जल्दी नौकरी या उच्च शिक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। डिग्री की अवधि कम होने से छात्रों को कम फीस देनी होगी। छात्र अपनी पढ़ाई को अपने अनुसार ढाल सकते हैं और अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं।

हालांकि, इस बदलाव के कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कि:- डिग्री की अवधि कम होने से पाठ्यक्रम में कमी आ सकती है, जिससे छात्रों को सभी महत्वपूर्ण विषयों को नहीं पढ़ने का मौका मिल पाएगा। जल्दी डिग्री पूरी करने के चक्कर में शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। अन्य देशों में ग्रेजुएशन की अवधि आमतौर पर तीन या चार साल होती है, इसलिए भारतीय डिग्री की मान्यता को लेकर कुछ सवाल उठ सकते हैं।

क्या यह बदलाव सही है?

यह एक जटिल सवाल है जिसका जवाब व्यक्तिगत राय पर निर्भर करता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह बदलाव छात्रों के हित में है क्योंकि इससे उन्हें समय और पैसा बचेगा। वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि यह बदलाव शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।

यह बदलाव क्यों?

वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करना। रोजगार के अवसर: छात्रों को जल्दी रोजगार प्राप्त करने में मदद करना। उच्च शिक्षा में सुधार: उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना।

इस बदलाव के क्या प्रभाव हो सकते हैं?

सकारात्मक प्रभाव:- छात्रों को जल्दी रोजगार मिल सकता है। उच्च शिक्षा अधिक किफायती हो सकती है। उच्च शिक्षा में अधिक विविधता आ सकती है। नकारात्मक प्रभाव: शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। कुछ छात्रों को जल्दबाजी में डिग्री पूरी करने के लिए दबाव महसूस हो सकता है।

विभिन्न विश्वविद्यालयों में नए नियमों का क्रियान्वयन अंतर-विश्वविद्यालय भिन्नता: विभिन्न विश्वविद्यालयों ने यूजीसी के नए नियमों को अलग-अलग तरीकों से अपनाया है। कुछ विश्वविद्यालयों ने इन नियमों को पूरी तरह से लागू कर दिया है, जबकि अन्य ने अभी भी कुछ बदलावों को लागू करना शुरू किया है। पाठ्यक्रम में बदलाव: कई विश्वविद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रमों में बदलाव किए हैं ताकि वे कम समय में अधिक से अधिक विषयों को कवर कर सकें। सेमेस्टर सिस्टम: कई विश्वविद्यालयों ने सेमेस्टर सिस्टम को अपनाया है ताकि छात्रों को अधिक लचीलापन मिल सके और वे अपनी पढ़ाई को अपने अनुसार ढाल सकें। ऑनलाइन शिक्षा: कई विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया है ताकि छात्र कहीं से भी और कभी भी पढ़ सकें।

समर्थन में तर्क-लचीलापन और छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण: कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये नियम उच्च शिक्षा को अधिक लचीला और छात्र-केंद्रित बनाएंगे। छात्र अपनी गति से पढ़ाई कर सकेंगे और अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकेंगे।

समय और धन की बचत: विशेषज्ञों का मानना है कि इन नियमों से छात्रों का समय और धन दोनों बचेगा। वे कम समय में अपनी डिग्री पूरी कर पाएंगे और जल्दी नौकरी या उच्च शिक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे।

अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप: कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये नियम भारतीय उच्च शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाएंगे।

नवाचार को बढ़ावा: ये नियम विश्वविद्यालयों को नए पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

आलोचना में तर्क---शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होना: कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन नियमों से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। छात्रों को कम समय में अधिक पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, जिससे उनकी समझ कमजोर हो सकती है। पाठ्यक्रम में कटौती: डिग्री की अवधि कम होने से कई महत्वपूर्ण विषयों को पाठ्यक्रम से हटाना पड़ सकता है। अन्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा: कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये नियम उन छात्रों के लिए अन्यायपूर्ण होंगे जो धीमी गति से पढ़ते हैं या जिनकी व्यक्तिगत परिस्थितियां उन्हें पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने से रोकती हैं। अंतरराष्ट्रीय मान्यता: कुछ विशेषज्ञों को चिंता है कि इन नियमों से भारतीय डिग्री की अंतरराष्ट्रीय मान्यता कम हो सकती है।

छात्रों की प्रतिक्रिया :- मिश्रित प्रतिक्रियाएं: छात्रों की प्रतिक्रियाएं मिश्रित रही हैं। कुछ छात्रों को लगता है कि नए नियमों से उन्हें समय और पैसा बचेगा, जबकि अन्य छात्रों को लगता है कि शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। चुनौतियाँ: कई छात्रों को पाठ्यक्रम में बदलाव और अधिक काम के बोझ के कारण मुश्किलें आ रही हैं। अवसर: कुछ छात्रों को नए नियमों के कारण नए अवसर मिल रहे हैं, जैसे कि जल्दी नौकरी या उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने का मौका।

अन्य देशों में उच्च शिक्षा के लिए समय सीमा

अधिकांश विकसित देशों में ग्रेजुएशन की अवधि तीन या चार साल होती है। हालांकि, कुछ देशों में दो साल की ग्रेजुएट डिग्री भी उपलब्ध हैं। यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका: अधिकांश अमेरिकी विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन की अवधि चार साल होती है। यूनाइटेड किंगडम: यूके में कई विश्वविद्यालय तीन साल की ग्रेजुएट डिग्री प्रदान करते हैं। ऑस्ट्रेलिया: ऑस्ट्रेलिया में भी अधिकांश विश्वविद्यालय तीन साल की ग्रेजुएट डिग्री प्रदान करते हैं। भारत की तुलना: भारत में ग्रेजुएशन की अवधि कम करने से भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली अन्य देशों की उच्च शिक्षा प्रणाली से अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकती है।

मान्यता: हालांकि, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत की डिग्री को अन्य देशों में मान्यता मिलती है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता क्या है।

यूजीसी के नए नियमों पर विशेषज्ञों की राय

यूजीसी के नए नियमों को लेकर विशेषज्ञों की राय काफी विविध है। कुछ विशेषज्ञ इन नियमों का समर्थन करते हैं तो कुछ इनकी आलोचना करते हैं। आइए जानते हैं विभिन्न विशेषज्ञों के क्या विचार हैं:-

विभिन्न मत: विशेषज्ञों की राय भी इस मामले में विभाजित है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नए नियम छात्रों के हित में हैं, जबकि अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी।

चिंताएं: कई विशेषज्ञों को इस बात की चिंता है कि जल्दी डिग्री पूरी करने के चक्कर में छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और कौशल हासिल करने का पर्याप्त मौका नहीं मिलेगा।

सुझाव: विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालयों को नए नियमों को लागू करते समय छात्रों की जरूरतों और क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

निष्कर्ष:--यूजीसी के नए नियमों ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नई बहस छेड़ दी है। यह बदलाव छात्रों, विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञों सभी के लिए एक चुनौती है। यह समय के साथ ही पता चलेगा कि ये नए नियम छात्रों के लिए फायदेमंद साबित होते हैं या नहीं। यह छात्रों, विश्वविद्यालयों और समाज पर दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा।

–प्रो. अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर,
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
विभागाध्यक्ष राजस्थान
विश्वविद्यालय

वासुदेव देवनानी का राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन से लौटने पर नागरिक अभिनंदन

'ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और जापान की यात्रा में भारतवंशियों, विदेशियों और खासकर राजस्थानियों का बड़ा स्नेह मिला'

अजमेर, (कासं)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का आस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन एवं इंडोनेशिया, जापान व सिंगापुर के स्टडी टूर से लौटने पर शुक्रवार को अजमेर में भव्य स्वागत किया गया। देवनानी जिले के पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन को सम्बोधित किया। उनके लौटने पर बड़ी संख्या में समर्थक व आमजन जुटे।

जानकारी के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का शुक्रवार को अजमेर लौटने पर विजयलक्ष्मी पार्क में नागरिक अभिनंदन किया गया। दर्जनों समाजों, संस्थाओं, हजारों समर्थकों ने उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए देवनानी ने कहा कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में भारत, राजस्थान, अजमेर और खासकर अजमेर उत्तर के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होना, सम्बोधन करना मेरे लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में भारत की पहचान एक सशक्त राष्ट्र के रूप में है। भारतीयों को आज पूरे विश्व में एक अलग सम्मान और स्नेह प्राप्त है।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का अजमेर में स्वागत किया गया।

- **विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जिले के पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन को सम्बोधित किया है**
- **जिस तरह भारत में मानवता, समानता और आपसी प्रेम है, वह इन देशों में भी देखने को मिला : वासुदेव देवनानी**

देवनानी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और जापान की यात्रा में भारतवंशियों, विदेशियों और खासकर राजस्थानियों का बड़ा स्नेह मिला। इन सभी देशों में भारतीय संस्कृति को बड़े सम्मान और आदर के रूप में देखा जाता है। जापान में रासलीला, कत्थक एवं कालबेलिया नृत्य बड़े प्रचलित हैं। इसी तरह सिंगापुर यूनिवर्सिटी में भी भारतीयता की झलक दिखाई दी। इंडोनेशिया व ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीयता पूरी तरह सम्मानित नजर आई। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र सबसे मजबूत लोकतंत्र है। जिस तरह भारत में मानवता, समानता और आपसी प्रेम है, वह इन देशों में भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों से इतना प्रेम करते हैं इन चारों देशों में सत्रह दिन की यात्रा में प्रतिदिन किसी न किसी भारतवासी के निवास पर बना भोजन ही किया। यह अतिथि देवो भव: की हमारी विपुल संस्कृति है जो विदेशों में भी कायम है। लोग घरों से टिफिन बना कर लाते थे। इन देशों में भारतीय आध्यात्म, योग एवं सनातन धर्म का भी विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि मैं आजीवन देश, समाज, राजस्थान और अजमेर उत्तर के लोगों की सेवा करता रहूंगा।

देवनानी का अजमेर आगमन पर किशनगढ़ में सभापति दिनेश सिंह, गेगल टोल पर महेन्द्र सिंह रावत, यूनिवर्सिटी तिराहे पर रमेश सोनी एवं अमित भंसाली ने समर्थकों के साथ सहित जिले की कई संस्थाओं और सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया।

राशिफल शनिवार 23 नवम्बर, 2024

पंडित अनिल शर्मा

मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2081, मघा नक्षत्र सायं 7:27 तक, ऐन्द्रयन योग दिन 11:41 तक, कौलव करण सायं 7:58 तक, चन्द्रमा आज सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-कर्क, बुध-वृश्चिक, गुरू-वृष, शुक्र-धनु, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज श्री काल भैरवाष्टमी, कालाष्टमी, प्रथमाष्टमी है।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 8:16 से 9:35 तक, चर 12:13 से 1:32 तक, लाभ-अमृत 1:32 से 4:10 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 6:57, सूर्यास्त 5:30

मेष
परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आपसी ईर्ष्या-वैमनस्यता के कारण परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

सिंह
मन:स्थिति ठीक रहेगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक खर्चों में वृद्धि होगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त कार्य करना पड़ सकता है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

वृष
घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति में प्रगति होगी।

कन्या
आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन हानि हो सकती है। घर-गृहस्थी के खर्चों में वृद्धि होगी। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी।

मकर
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

मिथुन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज नये-पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है और मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

तुला
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित धन प्राप्त होगा। चलते व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।

कुंभ
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगी। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक मामलों में संयम रखना ठीक रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग बढ़ेगा।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन
अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।

हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन, जोधपुर के पदाधिकारियों की बैठक एसोसिएशन के अध्यक्ष रतनाराम ठोलिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।

अध्यक्ष रतनाराम ठोलिया ने बताया कि बैठक में प्रमुख रूप से राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत पदों के अनुरूप न्यायाधिपतिगणों की नियुक्ति नहीं होने से न्याय प्राप्ति में हो रही देरी को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के नाम से प्रतिवेदन प्रेषित कर उच्च न्यायालय में न्यायाधिपतिगणों की नियुक्त किये जाने का निवेदन किया गया। साथ ही उल्लेखित किया गया कि आगामी वर्ष में लगभग चार से पांच न्यायाधिपति सेवानिवृत होंगे जिससे नियुक्त न्यायाधिपतिगणों की संख्या में ओर कमी होगी इसलिये शीघ्रता से ही नये न्यायाधिपतिगणों की नियुक्ति की जाये, जिससे मुवकिलों को शीघ्रता से न्याय प्राप्त हो सके।

- **बैठक में उच्च न्यायालय में न्यायाधिपतिगणों की नियुक्त किये जाने का निवेदन करने सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया**

बैठक में किराया अधिकरण के न्यायालय के संबंध में विचार-विमर्श करते हुए उच्च न्यायालय प्रशासन को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया, जिसमें मांग की गई कि वर्तमान में किराया अधिकरण का एक ही न्यायालय कार्यरत है, लेकिन किराया अधिकरण के मामलों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए सभी मामलों की समय पर सुनवाई नहीं हो पाती, जिससे मामलो में अनावश्यक रूप से देरी होती है व मुवकिलों को न्याय प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है, इसलिये जोधपुर महानगर न्याय क्षेत्र के लिए एक अतिरिक्त किराया अधिकरण के न्यायालय का गठन किया जाये।

इस अवसर पर आयोजित बैठक के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष रतनाराम ठोलिया, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र दाधीच, महासचिव शिवलाल बरवड़, सहसचिव विजेन्द्र पुरी, पुस्तकालय सचिव कांता राजपुरोहित, कोषाध्यक्ष विमल कुमार माहेश्वरी सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे।

पशुपालक की 59 भेड़ों को जंगली जानवर ने मारा

घटना की जानकारी मिलने पर पटवारी ने मौका मुआयना किया

जैसलमेर, (नि.सं.)। जैसलमेर जिले के खुईयाला गांव की कायम की ढाणी के एक पशुपालक की 59 भेड़ों को किसी जंगली जानवर ने मार डाला। घटना के दो दिन बाद पशुपालक रोजे खान को जानकारी मिलने पर उसके होश उड़ गए। रोजे खान की एक साथ 59 भेड़ों को मार डालने से उस पर रोजी-रोटी का संकट आ गया है। वहीं अन्य पशुपालक भी इससे दहशत में है।

खुईयाला गांव की कायम की ढाणी के पशुपालक रोजे खान पुत्र सुमार खान ने बताया कि उनकी 72 भेड़ें थी, जो चरने के लिए खुईयाला के निकट चारागाह की तरफ गई थी। दो दिन बीतने के बाद भी जब भेड़ें वापस नहीं लौटी तो भेड़ों की तलाश शुरू की। खुईयाला से करीब तीन किलोमीटर दूर एक स्थान पर बड़ी संख्या में भेड़ें मृत पाई गई, जिनके शरीर को पूरी तरह से नोचा हुआ था। यह मंजर देख कर उसके होश उड़ गए। रोजे खान ने आशंका जताई कि उनकी भेड़ों को किसी जंगली जानवर ने अपना शिकार बनाया है। रोजे खान ने जब भेड़ों की गिनती की तो 72 में से 59 भेड़ें मृत पाई गई। खुईयाला क्षेत्र के पशु पालकों को जब इस घटना का पता चला तो उनमें भी डर व्याप्त हो गया है। पशुपालकों ने जिला प्रशासन से अज्ञात जंगली जानवर का पता लगाकर राहत दिलाने की गुहार लगाई है। घटना की जानकारी मिलने पर पटवारी आदि ने मौका मुआयना कर मामले की जानकारी ली।